

प्रेषक,

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी, चम्पावत एवं चमोली

ग्राम्य विकास विभाग:

देहरादून:

दिनांक: 21 जनवरी, 06

विषय:— राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन बावत।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन बावत भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के क्रम में शासन स्तर से पत्र संख्या 89 / रा0ग्रा0रो0गा0यो0 / ग्रा0वि0वि0 / 05 दिनांक 3-12-2005, 1018 / रा0ग्रा0रो0गा0यो0 / ग्रा0वि0वि0 / 05 दिनांक 2-1-2006 तथा पत्र संख्या 19 / रा0ग्रा0रो0गा0यो0 / ग्रा0वि0वि0 / 05 दिनांक 16-1-2006 द्वारा सुस्पष्ट निर्देश यद्यपि जारी किये गये हैं तथापि दिनांक 2-2-2006 से ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरों के पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जाना है जिसके लिये संलग्न समय सारिणी के अनुसार सभी आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करा ली जाय।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 30-1-2006 को पूर्वान्ह में 11 बजे से 12 बजे के मध्य तीनों जनपदों की में की गयी तैयारियों की समीक्षा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी। कृपया समयबद्ध तैयारियाँ सम्पन्न कर आप स्वयं मुख्य विकास अधिकारी सहित उपस्थित रहें।

संलग्न:— समय सारिणी

भवदीया,

(विभा पुरी दास)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुश्रवण हेतु:—

1. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तरांचल।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तरांचल पौड़ी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को महोदय के अवलोकनार्थ।
4. अधिशासी निदेशक, उत्तरांचल ग्राम विकास संस्थान, रुद्रपुर, उ0सि0नगर।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल को दिनांक 30-1-2006 को पूर्वान्ह 11 से 12 बजे के मध्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु स्लॉट उपलब्ध काने हेतु।

विभा पुरी
(विभा पुरी दास)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु समय सारिणी

11/11/11

| क्रियाकलाप | समय सीमा |
|--|--|
| पंचायत पदाधिकारियों, सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों का अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम | 20-1-2006 |
| योजना के उद्देश्यों, गारन्टी के क्रियान्वयन पद्धति एवं लाभों का प्रचार-प्रसार | 20-1-2006 तक एवं तदपश्चात निरन्तर |
| फार्मों, प्रपत्रों एवं पंजीकाओं की छपाई एवं उपलब्धता <ul style="list-style-type: none"> मुद्रण कार्य विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्धता जॉब कार्डों का कोडिंग कार्य | 20-1-2006 28-1-2006 31-1-2006 से निरन्तर |
| ग्राम सभा की खुली बैठक जिसके एंजेण्डे में योजना की व्यापक जानकारी, पंजीकृत परिवारों को अनुमन्य विधिक गारन्टी एवं सुविधाओं से अवगत किया जाना, क्रियान्वयन के लिये विचार विमर्श, प्राथमिकताओं के अन्तर्गत योजनाओं का अभिज्ञान आदि सम्मिलित हों (हिन्दी में मुद्रित समस्त प्रचार सामग्रियों वितरित की जाय)। | 26-1-2006 |
| प्रमुख सचिव एवं आयुक्त द्वारा वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से तीनों जनपदों की तैयारी की समीक्षा | 30-1-2006 पूर्वाह्न 11:00 से 12:00 बजे के मध्य |
| ग्राम पंचायत स्तर तक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता | 31-1-2006 |
| ग्राम सभा द्वारा संस्तुत कार्यों के सापेक्ष अधिनियम की प्राथमिकताओं के आधार पर शैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स का निर्माण (आगणन सहित) | 31-1-2006 |
| प्रत्येक ग्राम पंचायत में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना की कार्ययोजना में स्वीकृत पर्याप्त संख्या में कार्य यथारिथति चालू रखे जाय अथवा आरम्भ किये जाय। | 1-2-2006 एवं लगातार |
| ग्राम सभा की खुली बैठक जिसमें अधिनियम के शुभारम्भ के साथ इच्छुक ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण प्रारम्भ किया जाना एवं मा० मुख्यमंत्री जी की वीडियो कान्फेसिंग। | 2-2-2006 |
| पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा/परीक्षण | 20-2-2006 तक |
| जॉब कार्डों का निर्गमन | 28-2-2006 |
| प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियों | 28-2-2006 |
| अतिरिक्त कार्मिकों एवं सेवाओं की उपलब्धता | 28-2-2006 |

जॉब कार्ड के निर्गत होने पर पंजीकृत परिवार के वयस्क सदस्य को विधिक रूप से रोजगार हेतु न करने का अधिकार है। तदनुसार रोजगार की वैधानिक गारन्टी इसी स्तर से प्रभावी होगी। इस को लागू करने के लिये यद्यपि 14 दिवस की अवधि उपलब्ध है परन्तु आवेदन करने के साथ ही उपलब्ध कराया जाना श्रेयस्कर होगा। 15 दिवस के भीतर अथवा अग्रिम प्रार्थना पत्र की स्थिति में तैथि जिस दिन से रोजगार चाहा गया है रोजगार उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में बेरोजगारी राज्य सरकार द्वारा दिया जाना होगा। बेरोजगारी भत्ता दिये जाने से बचा जाना होगा।